

प्रमुख अंतर-राज्यीय जल विवाद (ISWD)



संवैधानिक और विधिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 262: अंतर-राज्यीय जल विवादों के अधिनिर्णय का प्रावधान करता है। इसके तहत, संसद ने दो कानून बनाए: नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 और अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (ISWD) अधिनियम, 1956
- नदी बोर्ड अधिनियम, 1956: अंतर-राज्यीय नदियों के नियमन हेतु नदी बोर्डों की स्थापना
- ISWD अधिनियम, 1956: केंद्र सरकार ने दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जल विवादों के समाधान हेतु एक अस्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना की [वर्ष 2002 में संशोधित जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु 1 वर्ष की समय सीमा और निर्णय हेतु 3 वर्ष की समय सीमा अनिवार्य (सरकारिया आयोग)]
- राज्य सूची (प्रविष्टि संख्या 17): जल से संबंधित
- संघ सूची (प्रविष्टि संख्या 56): संसद के पास अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित व विकसित करने का अधिकार है यदि यह सार्वजनिक हित के लिये आवश्यक समझा जाता है।

